

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1584/2013/जयपुर

सहायक आयुक्त, वृत्त-बी, वाणिज्यिक कर, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्री मित्तल ऑटोमेटिव, एम.आई.रोड, जयपुर

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री आर.एन.गर्ग, अभिभाषक,

..... प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 56/अपील्स-II/आरवीएटी/जयपुर/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-बी, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23, 24, 55, एवं 58 के तहत पारित आदेश दिनांक 11.01.2012 में कायम मांग राशि रुपये 1,43,550/- को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्रों के विलम्ब से जमा करवाये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश में अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रुपये 99,000/- आरोपित की गई थी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में देय कर विलम्ब से जमा करवाये जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश में अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज रुपये 44,476/- आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर राशि रुपये 59/- कम जमा करवाये जाने के कारण ब्याज रुपये 15/- आरोपित करते हुए आदेश पारित किया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 07.03.2013 द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया एवं ब्याज को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी-राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है। उन्होंने सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुये अपीलीय अधिकारी के आदेश को खारिज करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. प्रत्यर्था व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया। उन्होंने आगे अपने कथन में कहा कि सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण से पूर्व प्रत्यर्था व्यवहारी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 30.03.2011 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिये दिनांक 31.03.2011 तक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में शास्ति व ब्याज को माफ किया गया है। इसी प्रकार आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा भी परिपत्र दिनांक 16.05.2011 के द्वारा दिनांक 16.05.2011 तक विवरण प्रपत्र जमा कराने पर शास्ति व ब्याज को माफ किया गया है।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 58 की शास्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या एफ.12(25) एफडी/टैक्स/11-169 दिनांक 30.03.2011 के द्वारा वर्ष 2009-10 के लिये दिनांक 31.03.2011 तक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में शास्ति एवं ब्याज की राशि को माफ किया गया है। अधिसूचना का सम्बन्धित भाग निम्नानुसार है :-

NOTIFICATION

No.F.12(25)FD/Tax/11-169

Jaipur, Dated: 30.3.2011

In exercise of the powers conferred by section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-2010, by the dealers who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 up to 31.03.2011.

8. इसी प्रकार आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.16()टैक्स/सीसीटी/11-241 दिनांक 16.5.2011 का बिन्दु संख्या 4 व 5 निम्न प्रकार है :-

Hon'ble Chief Minister (Finance Minister) at para 258 of the Budget Speech 2011-12 has announced that :-

4. **Levy of Penalty and Interest.**- The State Government vide notfn No. F.12(25)FD/Tax/11-01 dated 1-4-2011, as amended from time to time, have waived penalty and interest levied or likely to be levied on filing of late return and/or late payment of tax for the dealers who have submitted their all returns including annual return or audit report as the case may be, up to 16.5.2011. **Therefore, no penalty or interest shall be levied on late filing of return or late payment of tax against such dealer(s) on the condition that due tax has been deposited up to 16.5.2011 and all the returns including annual return or audit report, as the case may be, has been submitted up to 16.5.2011.**

5. **Procedure of Deemed Assessment.**- In all such cases, the AA shall verify the return in the manner prescribed in clause (3) above and shall make a note on the order sheet, after due verification that the net tax payable by the dealer, as per the return, has been deposited into the exchequer and all the returns including annual return or audit report, as the case may be, has been submitted by the dealer up to 16.5.2011, therefore, the dealer is being assessed with nil demand under the Deemed Assessment Scheme. Copy of such order sheet shall not be made available to the dealer unless directed by the Dy. Commissioner (Admn.)

9. हस्तगत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन/परीक्षण पश्चात यह निष्कर्षित किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.16()टैक्स/सीसीटी/11-241 दिनांक 16.5.2011 के निर्देशों की पालना नहीं करते हुए शास्ति का आरोपण किया गया है। शास्ति विधिक रूप से आरोपणीय ही नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(25) एफडी/टैक्स/11-169 दिनांक 30.03.2011 के द्वारा शास्ति एवं ब्याज माफ किये जा चुके थे।
10. हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 31.03.2011 से पूर्व ही दिनांक 12.07.2010 तक सभी विवरण प्रपत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे। ऐसी स्थिति में निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति प्रथम दृष्टया अविधिक थी, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है।
11. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, अतः नोटिस के अभाव में शास्ति आरोपण प्रथम दृष्टया अविधिक है।
12. अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 07.03.2013 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
13. निर्णय सुनाया गया।



(खेमराज)
अध्यक्ष